

International Research Journal of Management Science and Technology



International Research journal of Management Science & Technology

Vol 15 Issue 4

ISSN 2348 – 9367

Visit : www.irjmst.com for More Details

**International Research Journal of
Management Science &
Technology**

ISSN 2348 – 9367
A REFEREED JOURNAL OF



Explore Innovate Educate

**Shri Param Hans Education &
Research Foundation Trust**

www.IRJMST.com
www.SPHERT.org

**International Research Journal of Management Science
& Technology**

Vol 14

ISSUE 4

APRIL 2024

"Investigation of Zooplankton diversity at Parasdoh reservoir in Betul district of Madhya Pradesh"	3
Soni Nilesh Kumar* ,Dharsey Durgesh Nandini* ,Gawande Manohar Rao#.....	3
Irrigational suitability of some groundwater sources of Batadraba block of Nagaon district of Assam (India)	11
Dr. Mukut Moni Saikia	11
A STUDY OF LENDING TRENDS OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS IN INDIA WITH SPECIAL REFERENCE TO PRIORITY SECTOR	17
Vijay Kumar Gupta	17
The Impact of Recommendation Systems on Data Privacy.	21
Disha Tiwari, Dr. Deepti Sharma.....	21
Prediction of Cardiovascular Disease Using Machine Learning Algorithms	33
Mr. Bhoopendra Singh	33
Dr. Subodhini Gupta.....	33
Dr. R. K. Dixit.....	33
संशोधनी अमरावती विद्यालयाची शिक्षण व संशोधन क्रियात्मकतेचा विकास	48
शोभाची कुमारी शशि.....	48
SUSTAINABLE ASPECT OF NANO TECHNOLOGY	60
DR. LATA SHARMA.....	60
On the Transforming of Seismic Waves in Porus Media into Boundary Value Problems through Reflection-Refraction Coefficients 64	
Sonali Choukade.....	64

तकनीकी आधारित विद्यालयी शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान का योगदान

शोधार्थी कुमारी शशि

आर्यभट्ट राज विश्वविद्यालय (शिक्षा संकाय)

पंजीयन संख्या-17503602008

Email- shafisanjayasingh@gmail.com

Abstract (सार)

शिक्षा जीवनपर्यंत चलनेवाली प्रक्रिया है। शिक्षा के बिना मनुष्य का विकास संभव नहीं है। शिक्षा का अर्थ- ज्ञान, सुविचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा प्रौद्योगिकी दक्षता, विद्या इत्यादि को प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। वर्तमान युग तकनीकी युग हो गया है, मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र एवं प्रत्येक पहलु को तकनीक प्रभावित करता है, जिसमें शिक्षा भी प्रमुख है। विद्यालयों में शिक्षण को प्रभावकारी बनाने के लिए -कम्प्यूटर, रेडियो, प्रोजेक्टर, टेलीविजन, स्मार्ट कक्षा एवं भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है। शिक्षा सभी मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और सभी को उचित शिक्षा मिलना अनिवार्य है। सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएँ चलाई, जिनमें से एक है समग्र शिक्षा अभियान। केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना- समग्र शिक्षा शुरू की है, जिसमें वर्ष 2018-19 से सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा की तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल किया गया है। समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) घटक में कक्षा VI से XII तक के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है, जो बजटीय प्रावधान की उपलब्धता, अनुमोदित हस्तक्षेपों की प्रगति और राज्यों से प्रस्तावों की प्राप्ति पर विचारित है।

सर्व शिक्षा अभियान + राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान + शिक्षक शिक्षा = समग्र शिक्षा अभियान।

समग्र शिक्षा अभियान ने विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अभियान के माध्यम से, बच्चों को बुनियादी शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाती है जो उनके शैक्षिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समग्र शिक्षा अभियान में तकनीकी शिक्षा का महत्व बहुत उच्च है क्योंकि यह छात्रों को आधुनिक और तकनीकी दुनिया में अपनी जगह बनाने में मदद करता

है। तकनीकी शिक्षा उन्हें नवीनतम और उपयोगी दक्षताओं का संचार करती है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिजाइन और नवाचारिक तकनीकों का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करना। इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा छात्रों को आधुनिक रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा मानव समाज के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में जागरूकता, ज्ञान, और समृद्धि का संचार होता है। इस प्रकार, विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास को समृद्धि और समाज के उन्नति में अहम योगदान माना जाता है। समग्र शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस शोध पत्र में, हम विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास में समग्र शिक्षा अभियान की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
मुख्य बिंदु - समग्र शिक्षा अभियान, तकनीकी शिक्षा।

INTRODUCTION (परिचय)

केंद्रीय बजट, 2018-19 में घोषणा की गई थी कि स्कूली शिक्षा को पूर्व-प्राथमिक से बारहवीं कक्षा तक समग्र रूप से और बिना विभाजन के माना जाएगा। इस संदर्भ में, विभाग ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), म(आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर 2018 में स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना, समग्र शिक्षा शुरू की। यह योजना स्कूली शिक्षा को एक निरंतरता मानती है, जो शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुसार है। यह योजना न केवल शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि इसको यह सुनिश्चित करने के लिए भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ा गया है कि सभी बच्चों की एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो और जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं का भी ध्यान रखा गया हो और जो उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार भी बनाएं।

समग्र शिक्षा अभियान पूर्व संचालित योजनाओं को एकीकृत कर लाया गया है, जिसमें - सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा योजना को सम्मिलित किया गया है।

साहित्य समीक्षा -

विचित्रा पेगु(2020), ने अपने शोध पत्र में बताया कि समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य युवाओं की शिक्षा और मौलिक शिक्षण को बेहतर बनाना और समृद्ध करना है और तकनीकी शिक्षा सहित सीखने की सभी आयामों को सुदृढ़ करना है।

डॉ विजया लक्ष्मी(2019), के शोध पत्र अध्ययन से यह जानकारी प्राप्त हुई भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली शिक्षा में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती है। पि की दिशा में एक मील का पत्थर 'समग्र शिक्षा अभियान - स्कूली शिक्षा के एक एकीकृत योजना' का शुभारंभ है। यह स्कूली शिक्षा को एक ही सातल देखने का देश में पहला प्रयास है और इसका उद्देश्य दो टी यानी शिक्षक डिजिटल शिक्षा (प्रौद्योगिकी) पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्त सुधार करना है।

प्रदत्त विश्लेषण

समग्र शिक्षा के आईसीटी और डिजिटल पहल घटक में छठी से बारहवीं कक्षा व सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस घटक के तहत स्कूलों आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रद की जाती है। 'आईसीटी और डिजिटल पहल' के तहत गैर-आवर्ती/आवर्ती अनूट राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निम्नलिखित दो विकल्पों के लिए उपलब्ध है:

विकल्प -1 : इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले आईसीटी सुविधा का ल नहीं उठाया है, वे अपनी आवश्यकता और आवश्यकता के अनुसार आईसीटी स्मार्ट कक्षाओं का विकल्प चुन सकते हैं। 700 से अधिक नामांकन के मामले एक अतिरिक्त आईसीटी लैब पर भी विचार किया जा सकता है।

विकल्प -2 : इस विकल्प के तहत जो स्कूल पहले ही आईसीटी सुविधा का ला उठा चुके हैं, वे योजना के मानदंडों के अनुसार स्मार्ट कक्षाओं का लाभ उठा सक हैं।

- **लर्निंग रिकवरी पैकेज** के भाग के रूप में विशिष्ट राज्य प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को वर्ष 2022-23 से टैब के लिए प्रति शिक्षक 10000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। प्राथमिक कक्षाओं से संबंधित शिक्षकों के लिए कुल 1482565 टैब स्वीकृत किए गए हैं। अब तक, लगभग 1,79,498 उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को संबंधित योजनाओं के आईसीटी घटक के तहत कवरेज के लिए मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, सरकार ने डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लि विभिन्न पहल की हैं जैसे:—

- स्कूल प्रणाली के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम में आईसीटी - शिक्षकों और छात्रों के लिए आईसीटी पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है। छात्रों के पाठ्यक्रम को एक वर्ष के लिए 588 नवोदय विद्यालयों में संचालित किया गया था। तीस राज्यों के 805 एमआरपी/केआरपी को

संबंधित राज्यों में छात्रों और शिक्षकों के लिए आईसीटी पाठ्यक्रम के रोल-आउट पर उन्मुख किया गया था।

- ई-पाठशाला - पाठ्यपुस्तकों, ऑडियो, वीडियो, पत्रिकाओं और कई अन्य प्रिंट और गैर-मुद्रित सामग्रियों सहित सभी शैक्षिक ई-संसाधनों के प्रदर्शन और प्रसार के लिए एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) द्वारा ई-पाठशाला विकसित की गई है। पोर्टल और मोबाइल ऐप पर अब तक 3444 ऑडियो और वीडियो, 698 ई-बुक्स (ई-पब) और 504 फ्लिप बुक्स उपलब्ध कराई गई हैं।
- मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार (एनआरओईआर) - राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधनों का भंडार (एनआरओईआर) स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के सभी चरणों में सभी डिजिटल और डिजिटलीकरण योग्य संसाधनों को एक साथ लाने की एक पहल है। अब तक, पोर्टल पर 401 संग्रह, 2722 दस्तावेज़, 565 इंटरैक्टिव, 1664 ऑडियो, 2581 चित्र और 6105 वीडियो सहित 13635 फ़ाइलें उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एनआरओईआर पर संसाधनों का योगदान करने और अपने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए ओईआर बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

स्वयं:- (SWAYAM) 'स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स' (स्वयं) ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मंच है, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करता है और स्कूल (9वीं से 12वीं) से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक को कवर करता है। यह छात्रों, शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसे swayam.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) पोर्टल पर व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) पर पाठ्यक्रम प्रदान करके ई-लर्निंग विधियों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। SWAYAM प्लेटफॉर्म पर NIOS के 44 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं - माध्यमिक स्तर पर 14, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 16, 4 व्यावसायिक पाठ्यक्रम और डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed.) के 10 पाठ्यक्रम। एनसीईआरटी ने अब तक विभिन्न विषय क्षेत्रों में ग्यारहवीं-बारहवीं कक्षा के लिए 22 पाठ्यक्रम विकसित किए हैं।

स्वयं प्रभा:- 32 राष्ट्रीय चैनलों यानी स्वयं प्रभा डीटीएच-टीवी के माध्यम से शैक्षिक ई-सामग्री के प्रसारण के लिए उपग्रह संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। सीआईईटी-एनसीईआरटी एक डीटीएच टीवी चैनल यानी किशोर मंच (#31) के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है और उसने 24x7 शैक्षिक टीवी चैनल को 24x7 से प्रसारित करना शुरू कर दिया है। हितधारकों को उनकी

सुविधा के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिदिन चार घंटे का नया स्टॉट प्रसारित किया जाता है और 24 घंटे में 5 बार दोहराया जाता है। इसके अलावा, एनआईओएस शिक्षकों के लिए, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए और सांकेतिक भाषा के लिए 5 चैनल चला रहा है।

सीबीएसई की पहल:- सारांश सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों और अभिभावकों के लिए व्यापक आत्म समीक्षा और विश्लेषण का एक उपकरण है। यह उन्हें उपचारात्मक उपाय करने के लिए छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। SARANSH स्कूलों, शिक्षकों और अभिभावकों को करीब लाता है, ताकि वे छात्रों की प्रगति की निगरानी कर सकें और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकें। यह स्कूलों को विभिन्न स्तरों पर सभी सीबीएसई स्कूलों के प्रदर्शन की तुलना करने में मदद करता है और माता-पिता को स्कूल राज्य, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर अपने बार्ड के प्रदर्शन की तुलना करने में भी मदद करता है। यह वर्तमान में मानक IX - XII के लिए उपलब्ध है और 2007 से मानक X के प्रदर्शन और 2009 से वर्तमान शैक्षणिक सत्र तक मानक XII के प्रदर्शन का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।

केवीएस की पहल:- (KVS) सभी केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी से बारहवीं कक्षा के छात्रों को आईसीटी कौशल प्रदान किया जाता है। डिजिटल मोड के माध्यम से प्रभावी शिक्षण की सुविधा के लिए देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में 12011 ई-क्लासरूम (9711 ई-क्लासरूम स्थापित और 2300 प्रक्रियाधीन) स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, देश भर में 276 केवी में 276 डिजिटल लैंग्वेज लैब और 1137 कंप्यूटर लैब स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, गणित और विज्ञान में ई-सामग्री के साथ प्री-लोडेड टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट ई-प्रज्ञा शुरू किया गया है। गणित और विज्ञान में कक्षा संचालन के लिए आठवीं कक्षा के छात्रों और शिक्षकों के बीच 5076 टच टैबलेट वितरित किए गए हैं।

ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड:- भारत सरकार द्वारा 9वीं कक्षा से स्नातकोत्तर स्तर तक देश भर में लगभग 15 लाख कक्षाओं में इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड प्रदान करने की पहल की गई है, जहां वे सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों/प्रोफेसरों से व्याख्यान प्राप्त कर सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण ई-पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों की समग्र सीखने की प्रक्रिया और अनुभव को बढ़ाने के लिए सामग्री।

राष्ट्रीय विकास में मूलभूत कौशलों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए, 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत घोषणा की गई थी कि 2026-27 तक देश के हर बच्चे को अनिवार्य रूप से ग्रेड 3 में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का शुभारम्भ किया जाएगा। इस संदर्भ में, समग्र शिक्षा के तहत 5 जुलाई, 2021 को

“बेहतर समझ और संख्या ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत)” का शुभारम्भ किया गया है।

तकनीकी शिक्षा का महत्व

तकनीकी शिक्षा 21वीं सदी में सफलता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है। यह छात्रों को डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने, समस्याओं को हल करने, और रचनात्मक रूप से सोचने में सक्षम बनाता है। तकनीकी शिक्षा से छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त होते हैं।

एसएसए में तकनीकी शिक्षा

एसएसए के तहत, सरकार ने स्कूलों में कंप्यूटर लैब और इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा, सरकार ने शिक्षकों को डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने और छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया है।

विद्यालयी शिक्षा में तकनीकी शिक्षा का योगदान

तकनीकी शिक्षा ने विद्यालयी शिक्षा में कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं।

- **छात्रों की सीखने की क्षमता में सुधार:** तकनीकी शिक्षा ने छात्रों को अधिक सक्रिय और इंटरैक्टिव तरीके से सीखने में मदद की है। डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके, छात्र जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझ सकते हैं और विभिन्न विषयों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- **शिक्षकों की प्रभावशीलता में वृद्धि:** तकनीकी शिक्षा ने शिक्षकों को अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने में मदद की है। डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके, शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान कर सकते हैं, और छात्रों की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं।
- **शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि:** तकनीकी शिक्षा ने दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार किया है। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से, ये छात्र भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

डेटा और साक्ष्य (Data and Evidence)

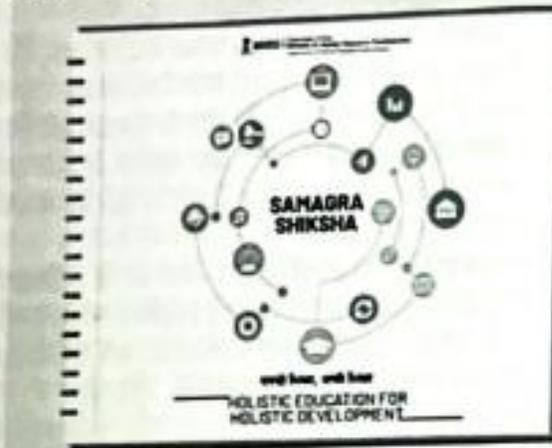
- एसएसए के तहत, भारत सरकार ने 1.5 लाख से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित किए हैं।
- 2020 तक, भारत में 10 लाख से अधिक शिक्षकों को डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया गया था।

- एक अध्ययन में पाया गया कि तकनीकी शिक्षा का उपयोग करने वाले स्कूलों में छात्रों के सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि तकनीकी रूप से सक्षम शिक्षक कक्षा में अधिक आकर्षक और प्रभावी ढंग से पढ़ा पाते हैं।

सरकारी आंकड़े (Government Data)

- **कंप्यूटर लैब की स्थापना:** एसएसए के तहत भारत सरकार ने देश भर के 1.5 लाख से अधिक स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित किए हैं।
- **शिक्षक प्रशिक्षण:** 2020 तक, केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख से अधिक शिक्षकों को डिजिटल उपकरणों के उपयोग और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

अनुसंधान अध्ययन (Research Studies)



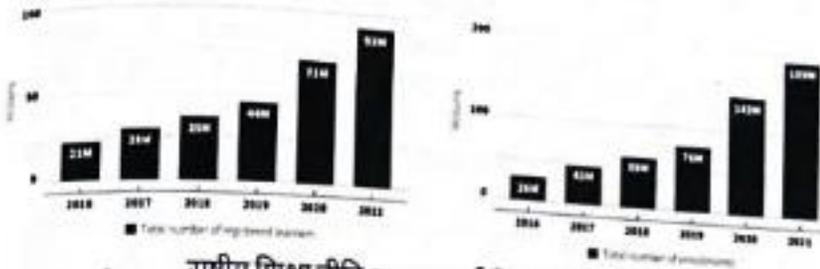
- **तकनीकी शिक्षा का प्रभाव:** एक शोध अध्ययन में पाया गया कि तकनीकी शिक्षा का उपयोग करने वाले स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन में उन स्कूलों के छात्रों की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जहाँ तकनीकी शिक्षा शामिल नहीं थी। इस अध्ययन में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों में परीक्षा परिणामों का विश्लेषण किया गया।

Fig. डिजिटल एजुकेशन में बढ़ोतरी

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य:

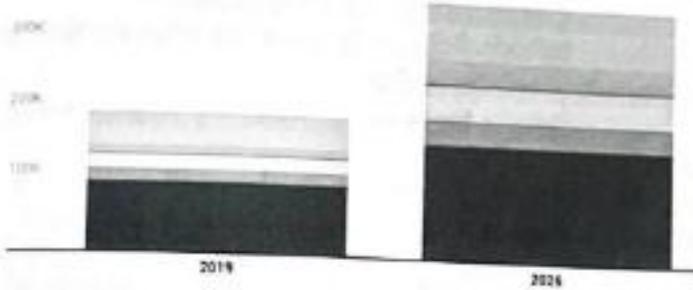
More learners are accessing online learning

(The number of online learning in India continues to increase over the years)



- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) की सिफारिशों को लागू करना;

■ Online e-learning ■ LMS* ■ Mobile e-learning ■ Rapid e-learning ■ Virtual classroom ■ Others



*LMS refers to learning management systems

Chart: Bay Atlantic University - Created with Datawrapper

- बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 को लागू करना;
- प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा;
- मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान पर जोर;
- विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशल प्रदान करने के लिए समग्र, एकीकृत, समावेशी और

गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम व अध्यापन पर जोर;

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा परिणाम में वृद्धि;
- स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को दूर करना;

- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना;
- तकनीकी शिक्षा के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना
- बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना
- शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्टेट काउंसिल्स फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी)/स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (डाइट) को मजबूत बनाना और सुधार;
- शिक्षा के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना व स्कूलिंग प्रावधानों में मानदंडों का रखरखाव और
- व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना।

डिजिटल पहल:

- हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहायता सहित स्कूलों में नई आईसीटी पहलों को मंजूरी।
- ई-सामग्री और डिजिटल संसाधन निर्माण
- डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शाला कोष, दीक्षा और अन्य केंद्रीय कार्यक्रम
- डिजिटल शिक्षण सामग्री निर्माण, नई शिक्षाशास्त्र और क्षमता निर्माण।

समग्र शिक्षा की विशेषताएं:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के आधार पर समग्र शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं:

1. समग्र दृष्टिकोण: समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के पूरे स्पेक्ट्रम, प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक, को एक सातत्य मानकर शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। इसका उद्देश्य छात्रों को एक सहज और एकीकृत शिक्षण अनुभव प्रदान करना है।
2. समावेशी शिक्षा: यह योजना समावेशी शिक्षा पर जोर देती है, जिसमें वंचित पृष्ठभूमि, हाशिए पर रहने वाले समुदायों और विकलांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाती है।
3. मूलभूत कौशल पर ध्यान: समग्र शिक्षा साक्षरता और संख्यात्मकता जैसे मूलभूत कौशल पर दृढ़ता से जोर देती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान ये आवश्यक कौशल हासिल कर ले।

4. शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: योजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानती है। यह शैक्षणिक कौशल को बढ़ाने और प्रभावी शिक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर केंद्रित है।
5. गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा: समग्र शिक्षा का उद्देश्य एक सुरक्षित, अनुकूल और प्रेरक शिक्षण वातावरण बनाने के लिए स्कूलों के बुनियादी ढाँचे में सुधार करना है। इसमें स्वच्छ और कार्यात्मक कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान शामिल हैं।
6. प्रौद्योगिकी का उपयोग: यह योजना शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी एकीकरण को प्रोत्साहित करती है। यह नवीन शैक्षणिक दृष्टिकोणों का समर्थन करने और सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए डिजिटल उपकरणों और संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देता है।
7. व्यावसायिक शिक्षा: समग्र शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को पहचानती है और इसका उद्देश्य स्कूली पाठ्यक्रम में इसके एकीकरण को बढ़ावा देना है। यह छात्रों को नौकरी बाजार की मांगों के अनुरूप व्यावहारिक कौशल से लैस करने पर केंद्रित है।
8. सामुदायिक भागीदारी: यह योजना शिक्षा प्रक्रिया में माता-पिता, समुदाय के सदस्यों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देती है। यह निर्णय लेने और स्कूल गतिविधियों की निगरानी में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के गठन को प्रोत्साहित करता है।
9. निगरानी और मूल्यांकन: समग्र शिक्षा हस्तक्षेपों और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन के महत्व पर जोर देती है। यह प्रगति को ट्रैक करने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डेटा-संचालित दृष्टिकोण का उपयोग करने को बढ़ावा देता है।
10. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान : समग्र शिक्षा शिक्षकों और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता देती है। यह एससीईआरटी और डीआईईटी जैसे शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करते हुए शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है। एससीईआरटी गतिशील और आवश्यकता-आधारित कार्यक्रमों को सुनिश्चित करते हुए, सेवाकालीन और सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल संस्थान बन जाता है। यह योजना विज्ञान और गणित सीखने के लिए राष्ट्रीय अविष्कार अभियान और

प्राथमिक स्तर पर मूलभूत कौशल के लिए पढ़े भारत, बढ़े भारत कार्यक्रम का समर्थन करती है। यह 5000 रुपये से लेकर प्रत्येक स्कूल को 20000 रु. का पुस्तकालय अनुदान भी प्रदान करता है। ये पहल एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जो समग्र विकास को बढ़ावा देती है और छात्रों को आवश्यक कौशल के साथ सशक्त बनाती है।

11. बालिका शिक्षा पर ध्यान: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का उन्नयन: केजीबीवी को कक्षा 6-8 से कक्षा 6-12 तक उन्नत किया जाएगा, जिससे लड़कियों के लिए पर्याप्त शैक्षिक अवसर उपलब्ध होंगे। आत्मरक्षा प्रशिक्षण: उच्च प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की लड़कियों के आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे उन्हें उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए आवश्यक कौशल के साथ सशक्त बनाया जाएगा। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता: 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' पहल के प्रति एक मजबूत समर्पण, बालिकाओं को बचाने और शिक्षित करने के महत्व पर जोर देना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

12. आरटीई अधिनियम के तहत समावेशन पर ध्यान : आरटीई अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित आवंटन किए जाते हैं जैसे रु। वर्दी के लिए 600 रु. पाठ्यपुस्तकों के लिए 250/400, और सक्रिय पाठ्यपुस्तकें पेश की गईं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समर्थन में वृद्धि और विशेष आवश्यकता वाले लड़कियों के लिए वजीफा।

13. खेल और शारीरिक शिक्षा पर ध्यान: पाठ्यचर्या में खेल एकीकरण - खेल उपकरण के प्रावधान की लागत रु. प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5000 रु. उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,000, और रु. माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25,000। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा में खेलों के महत्व को बढ़ावा देना और उजागर करना है।

चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा

हालांकि तकनीकी शिक्षा ने विद्यालयी शिक्षा में सकारात्मक बदलाव लाए हैं, फिर भी कुछ चुनौतियाँ हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

- **बुनियादी ढांचे की कमी:** भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा, जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी है।
- **शिक्षकों का प्रशिक्षण:** सभी शिक्षकों को अभी तक तकनीकी उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

- डिजिटल विभाजन: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों के पास अक्सर घर पर कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग नहीं होता है, जिससे उनके सीखने के अवसर कम हो जाते हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सरकार को बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण और डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए कार्यक्रमों पर ध्यान देना चाहिए।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, समग्र शिक्षा अभियान के तहत तकनीकी शिक्षा एक सफल पहल साबित हुई है। इसने छात्रों की सीखने की क्षमता में सुधार किया है, शिक्षकों की प्रभावशीलता बढ़ाई है, और शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि की है। हालांकि, अभी भी कुछ चुनौतियों का समाधान किया जाना बाकी है। भविष्य में, सरकार को तकनीकी शिक्षा को और मजबूत करने और सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है।

Reference (संदर्भ सूची)

- <https://hi.vikaspedia.in/education/policies-and-schemes/%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE>
- <https://dsei.education.gov.in/scheme/ict-samagra#>
- <https://vikaspedia.in/education/policies-and-schemes/samagra-shiksha>
- <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1562596>
- <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1562596>
- <https://setu.tutor.co/blog/samagra-shiksha/#:~:text=Quality%20infrastructure%3A%20Samagra%20Shiksha%20a,ims,laboratories%2C%20and%20other%20necessary%20facilities.>
- <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.weforum.org%2Fagenda%2F2022%2F01%2Fonline-learning-courses-reskill-skills-gap%2F&psig=AOvVaw115ep44ZWgEPzAKHz7CjRe&ust=1713864702707000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIOjRxqFwoTCKix24zAIYUDFOAAAAAAdAAAAABAE>
- https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsamagra.education.gov.in%2Fimages%2Fbrochure.jpg&tbnid=AlbwrYTAXD0p1M&vet=1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsamagra.education.gov.in%2F&docid=CWZCQrGLMVLK_M&w=360&h=275&hl=en_GB&source=sh%2Fx%2Fim%2Fm1%2F5&kgs=239c9fa4eb09c401&shem=trie
- <https://bau.edu/blog/wp-content/uploads/2021/01/projectred-annual-growth-of-the-online-learning-market-1024x586.png>